भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2405
13/03/2026 को उत्तरार्थ

विषयः एमएसपी पर समिति द्वारा अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करना

2405. श्री रामजी लाल सुमनः

क्या **कृषि एवं किसान कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या किसानों की उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) सुनिश्चित करने हेतु 12 जुलाई, 2022 को गठित समिति में अधिकतर दफ्तरशाह शामिल थे, जो किसानों के मुद्दों के संबंध में निर्णय लेने और रूपरेखा निर्धारित करने के लिए जिम्मेदार थे;

(ख) समिति एवं उप-समितियों की बैठकों का तिथि-वार ब्यौरा और निर्णय क्या हैं;

(ग) क्या उक्त समिति अत्यंत शिथिल तरीके से कार्य कर रही है जिससे किसानों का अहित हो रहा है और उन्हें अभी भी उनकी उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिल रहा है; और

(घ) क्या सरकार उक्त समिति का अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए समय-सीमा तय करने पर विचार करेगी?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री भागीरथ चौधरी)

(क) से (घ): सरकार ने जुलाई 2022 में एक समिति का गठन किया, जिसमें राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता किसानों सहित किसानों के प्रतिनिधि, किसान सहकारी समिति/समूह के प्रतिनिधि, केंद्र सरकार के प्रतिनिधि और राज्य सरकारों के पर्याप्त प्रतिनिधि, प्रख्यात कृषि अर्थशास्त्री और वैज्ञानिक आदि शामिल थे। इस समिति को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने; प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने; और देश की परिवर्तनशील आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए फसल पैटर्न में बदलाव करने का अधिदेश सौंपा गया था। अपनी स्थापना के बाद से, समिति इन प्रमुख मुद्दों पर विचार-विमर्श करने और कार्रवाई योग्य सिफारिशें तैयार करने के लिए नियमित बैठकें कर रही है। अब तक, 6 मुख्य समिति बैठकें और 40 उप-समिति बैठकें आयोजित की जा चुकी हैं।

*****